

देश की अपार सजा

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02

अंक : 87

जौनपुर, शुक्रवार 22 दिसम्बर 2023

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य : 2 रूपया

सीएम योगी बोले-बखिरा के पीतल बर्तन उद्योग को विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाएगा

एजेन्सी संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि संतकबीरनगर के बखिरा करबे के पीतल बर्तन उद्योग को विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाएगा। जिले के बघौली ब्लॉक के ग्राम करौदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की भारत को 2047 तक भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का अभियान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबको जोड़ने की मुहिम है।

सीएम योगी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में हम एक नव भारत



का दर्शन कर रहे हैं और भारत को एक वैश्विक भारत का सम्मान प्राप्त हो रहा है। जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बखिरा के पीतल बर्तन उद्योग को विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने समाज में संत कबीर के मूल्यों व

आदर्शों, समता, सच्चवाना एवं समरसता की स्थापना और शोध को बढ़ावा देने के लिए संत कबीर अकादमी का निर्माण कराया है। वर्तमान बजट में हमने प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली के अवसर पर फ्री में भी सिलेंडर देंगे। मुख्यमंत्री

ने कहा, आज के भारत के पास राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी होने के साथ ही वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से पूरे देश में एक साथ प्रारम्भ हुई थी। वहीं, उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत लखीमपुर खीरी और सोनभद्र जिले से हुई थी। उन्होंने कहा कि यात्रा के अंतर्गत 536 मोदी गारंटी वीडियो वैन चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में अब तक 1072 कार्यक्रम कर चुकी हैं। भारत की आजादी के अग्रदूत और जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती से शुरू हुई यह यात्रा 26 जनवरी 2024

तक पूरे देश के अंदर चलेगी। योगी ने कहा कि यह यात्रा पूरे देश के अंदर सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में निकल रही है। यात्रा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपनी सफलता की कहानी स्वयं बता रहे हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं में पात्रता श्रेणी में आने वाले लोगों का यात्रा के अंतर्गत ही फार्म भी भरा जा रहा है और समयबद्ध तरीके से उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पिछले साढ़े 6 वर्ष में राज्य में 55 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिया गया है। तीन करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय मिला है। एक करोड़ 75 लाख से अधिक माताओं और बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में रसोई गैस सिलेंडर दिया गया है।

सीएम नीतीश ने बोधगया में परम पावन दलाई लामा से की मुलाकात, महाबोधि मंदिर में की पूजा-अर्चना

एजेन्सी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोधगया के तिब्बतियन मोनेस्ट्री पहुंच कर बौद्ध धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परम पावन दलाई लामा जी को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया और उन्हें नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री को दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री ने भी परम पावन दलाई लामा जी के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की। परम पावन दलाई लामा जी से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जब भी यहां आते हैं तो हम आपसे मिलने आते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं। सभी धर्मों के प्रति हमलोगों का सम्मान है। बौद्ध धर्म के प्रति भी हमलोगों का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने परम पावन दलाई लामा जी को वैशाली में बनने वाले बुद्ध स्म्यक

दर्शन संग्रहालय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री के आग्रह को परम पावन दलाई लामा जी ने स्वीकार किया। इसके पश्चात् तिब्बतियन



मोनेस्ट्री में ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सच मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके पश्चात् महाबोधि मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने महाबोधि महाविहार एवं बोध टैपल टैपल मैनेजमेंट कमिटी कार्यालय में 180 केंडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया। साथ ही महाबोधि मंदिर के उत्तर दिशा में पीतल से निर्मित भव्य द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने

महाबोधि मंदिर के आउटर बाउंड्री रेंलिंग का भी शिलान्यास किया। इसके पश्चात् महाबोधि मंदिर में मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बोधि वृक्ष की भी पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एसएम, गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, बोधगया टैपल मैनेजमेंट कमिटी की सचिव महाश्वेता महारथी, बोधगया टैपल मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य अरविंद सिंह, चीफ मॉक चालीन्दा भंते समेत वरीय पदाधिकारी, भंतेगण और बौद्ध श्रद्धालुगण मौजूद थे।

अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, राममंदिर में रामलला का किया दर्शन

एजेन्सी अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं। जहां पहुंचने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद सीएम योगी राममंदिर पहुंचे। जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आरती में शामिल होकर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री राममंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। बता दें कि राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसकी शुरुआत 18 जनवरी से हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण

वरण, वास्तु पूजन से होगा। 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा अयोध्या में नगर भ्रमण पर निकलेगी। 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इन्हीं के बीच आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। जहां सीएम राममंदिर निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीएम अन्य विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इससे पहले सीएम योगी दो दिनों का अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करने केन्द्रिय मंत्रियों के साथ आए थे। इस महीने में सीएम योगी का दूसरी बार अयोध्या आगमन हुआ है। सीएम के आने से पहले मंगलवार को आरएसएस के कई शीर्ष



पदाधिकारी अयोध्या पहुंचे। तीर्थ क्षेत्र भवन में बैठक कर तैयारी की गहन समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि पीएम 30 दिसंबर को

अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, शीत कालीन सत्र में 74 प्रतिशत कामकाज

एजेन्सी नयी दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ लोकसभा का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया है। निर्धारित तिथि के अनुसार, 4 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र को शुक्रवार तक चलना था। लेकिन, एक दिन पहले 21 दिसंबर को ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयोग (ईसी) मामले की जांच कर दिया। गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयोग (ईसी) मामले की जांच कर दिया। गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयोग (ईसी) मामले की जांच कर दिया। गुरुवार को लोकसभा ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, मुख्य निर्वाचन आयोग (ईसी) मामले की जांच कर दिया।

अध्यक्ष ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि वर्तमान चौदहवें सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 74 प्रतिशत रही। लोकसभा के चौदहवें सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 18 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एवं नितिन आर्युक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय अवधि) विधेयक - 2023 और प्रत्येक और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक-2023, को पारित कर दिया। लोकसभा

के दौरान 14 बैठकें हुईं जो लगभग 61 घंटे 50 मिनट तक चलीं। सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 74 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए एवं भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक-2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक -2023 और दूरसंचार विधेयक-2023 सहित 18 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को तथा वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को मतदान में उपरांत पारित किया गया। बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 55

तारकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। निदेश 73क के अधीन 33 वक्तव्य दिए गए और संसदीय कार्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित कुल 34 वक्तव्य दिए गए। बिरला ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान कुल 1930 दस्तावेज सभा के पटल पर रखे गए। सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में सभी दलों के नेताओं और सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

संजय सिंह बने डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष

एजेन्सी नयी दिल्ली भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के नए अध्यक्ष संजय सिंह बने। कई बार लंबित हुए चुनावों में उनके पैलन ने अधिकांश पद पर आसन जीत दर्ज की जिससे निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के हाथों में अप्रत्यक्ष रूप से महासंघ का नियंत्रण आ गया। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय को 40 जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी अनिता श्योराण को सात मत मिले। संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्य

क्ष बने थे। चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह ने कहा कि अब राष्ट्रीय शिविर (कुश्ती के लिए) आयोजित किए जाएंगे। जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वे राजनीति कर सकते हैं, जो कुश्ती करना चाहते हैं वे कुश्ती करेंगे। बृजभूषण सिंह के दामाद विशाल सिंह ने कहा कि हमारे पूरे पैलन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा, श्रद्धाएं सभी पैलन के सीते हैं। गिनती चल रही है तो अधिकारिक नंबर जल्द ही आ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में कुश्ती को नुकसान हुआ। हमारे खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन कर सकते थे।

पीएम मोदी को जेबकतरा बोलने पर बर्द्धी राहुल गांधी की मुश्किलें...दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया 8 दिन का समय

एजेन्सी नयी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई कथित 'जेबकतरा वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी किये गये नोटिस पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। कांग्रेस नेता ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए 'जेबकतरा और अन्य टिप्पणियां की थी। अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गां

गी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के 'कदाचार को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना क अनुरोध किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान 'उचित नहीं हैं और निर्वाचन रहा है और यहां तक कि गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मीनू पुष्करणा की पीठ ने आदेश दिया, 'यह मानते हुए कि जवाब



दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर यथासंभव शीघ्रता से आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। अदालत ने

कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में निर्वाचन आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि गांधी ने 22 नवंबर को एक भाषण दिया था जिसमें प्रधानमंत्री सहित 'उच्चतम सरकारी पदोपश पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ 'गंभीर आरोपश लगाए गए थे और उन्हें 'जेबकतरा के रूप में संदर्भित किया गया था।

बिहार: पटना में अज्ञात बदमाशों ने महिला कांस्टेबल को मारी गोली

एजेन्सी पटना। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में मनचले द्वारा एक महिला कांस्टेबल को गोली मारी है। चिकित्सकों ने उन्हें खतरने से बाहर बताया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि ये दोनों एलसीटी घाट पर थी। इस दौरान पम्मी खातून वीडियो बना रही थीं और किसी ने गोली मार दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिल पायी है, पुलिस जांच कर रही है। गंगा पथ पर मोबाइल से रील्स बना रही थी। इसी दौरान किसी ने फायरिंग

कर दी। इससे महिला कांस्टेबल पम्मी खातून को बायें हाथ में गोली लग गयी। आनन फानन में इन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया जा रहा है। चिकित्सकों ने उन्हें खतरने से बाहर बताया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि ये दोनों एलसीटी घाट पर थी। इस दौरान पम्मी खातून वीडियो बना रही थीं और किसी ने गोली मार दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिल पायी है, पुलिस जांच कर रही है। गंगा पथ पर मोबाइल से रील्स बना रही थी। इसी दौरान किसी ने फायरिंग

दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को राहत नहीं, 10 जनवरी तक बढ़ाई हिरासत

एजेन्सी नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि गुरुवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समान) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक

ई-कॉपी अदालत के निर्देश के अनुसार 'आप' नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि पिछले सभी आरोपपत्रों की प्रतियों के अलावा दस्तावेजों और पांचवीं अभियोजन शिकायत की प्रति को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा, '10 जनवरी को सूचीबद्ध करें, जब मुख्य मामले की सुनवाई निर्धारित है। न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई जाती है।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन

एजेन्सी/नयी दिल्ली। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने संसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यहां विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के साथ ही देश की विभिन्न हिस्सों में भी किया जाएगा।

छात्रों के खिलाफ जांच पर पुनर्विचार करेगा जेएनयू : वाइस चांसलर

एजेन्सी नयी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कुलपति शांतिश्री पंडित ने बृहस्पतिवार को कहा कि पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चार छात्र संध के प्रतिनिधियों और 12 छात्रावास के अध्यक्षों के खिलाफ शुरू की गई सभी प्रॉक्टोरियल जांच पर विश्वविद्यालय प्रशासन पुनर्विचार करेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूसयू) के प्रतिनिधियों और

छात्रावास के अध्यक्षों को 19 सितंबर को कुलपति के आवास के बाहर विशेष प्रदर्शन करने को लेकर पिछले महीने एक जांच नोटिस भेजा गया था। हालांकि, छात्रों के संगठन ने कहा कि वह 'थोड़ी सांत्वना से खुश नहीं है। कुलपति ने सोमवार को जेएनयूसयू प्रतिनिधियों और छात्रावास अध्यक्षों के साथ बैठक की और पानी की कमी के विरोध को लेकर किए गए प्रदर्शन के खिलाफ शुरू की गई प्रॉक्टोरियल

जांच को वापस लेने के लिए जेएनयूसयू की अपील पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। हालांकि, जेएनयू प्रशासन द्वारा चल रही अन्य पूछताछ पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। कुलपति को 15 दिसंबर को सौंपे गए ज्ञापन में जेएनयूसयू ने कार्रवाई को कठोर और मनमाना बताते हुए विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ चल रही सभी जांच को वापस लेने की मांग की थी। छात्रावास अध्यक्षों ने एक बयान में कहा, 'हम, जेएनयू के

छात्रावास अध्यक्षों ने छात्रावास समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की उम्मीद को लेकर 18 दिसंबर को कुलपति के साथ बैठक की। कुलपति ने हमें सूचित किया कि सभी प्रॉक्टोरियल नोटिसों पर अपील चरण में पुनर्विचार किया जाएगा। जेएनयूसयू ने 23 दिसंबर को कैंपस में मशाल मार्च का आह्वान किया है, जिसमें चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल को वापस लेने की मांग की गई है।

सम्पादकीय

ज्ञानवापी हिन्दू आस्था का प्रश्न

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रही कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हिन्दू पक्ष को काफ़ी सान्त्वना मिली है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षणष्के खिलाफ याचिका समेत मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं कोधुकरा दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 1991 के वाराणसी कोर्ट में दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य मानते हुए वाराणसी की अदालत को 6 माह के भीतर फैसला देने का निर्देश दिया है। वर्ष 1991 में एक केस फाइल किया गया था। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। यह केस सोमनाथ व्यास, रामनारायण शर्मा और हरिहर पांडे की ओर से दाखिल किए गए थे। इस केस में दावा किया गया था कि मस्जिद जहां बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है। इसलिए मुस्लिम धर्मस्थल को हटाकर उसका कब्जा हिन्दुओं को सौंपा जाए। घमस्जिद को लेकर पहलाघ विवाद 1809 में हुआ था जो साम्प्रदायिक दंगों में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ था जिसका निर्णय 1937 में आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने मस्जिद को वक्फ प्रोपर्टी माना।

12 सितम्बर, 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी–देवताओं की पूजा की मांग को लेकर दायर की गई पांच महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दीं। जब 1991 में ज्ञानवापी मामले में पहला मुकदमा दायर हुआ तो उसके कुछ महीने बाद सितम्बर 1991 में तत्कालीन पी.वी. नधरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल कानून बना दिया। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयो्ध या का मामला उस वक्त कोर्ट में था इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल छह महीने के लिए ही होगी। उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में शृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए । 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 32 वर्ष बाद मुकदमे की सुनवाई का आदेश दिया है और कहा है कि 1991 का उपासना स्थल कानून इस घसविल वाद में बाधित नहीं है। अब जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जा चुकी है और उसी के आधार पर स्वामित्व विवाद का हल निकल सकेगा और करोड़ों हिन्दुओं की आस्था जीवंत हो उठेगी। अब वाराणसी कोर्ट 6 माह में अपना फैसला सुनाएगा। हिन्दू पक्ष के वकीलों को उम्मीद है कि अब वजुखाने का सर्वे भी होगा। मेरा अमी भी यह दुःद मत है कि काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित ज्ञानवापी क्षेत्र को मुस्लिम बन्धुओं को हिन्दुओं को सौंप देना चाहिए और स्वतन्त्र भारत की एकता व 'गंगा-जमुनी' तहजीब में इजाफा करने के लिए अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। काशी या बनारस हिन्दू मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शंकर द्वारा बसाया गया वह स्थान है जिसमें शहनाई वादन के शहंशाह उस्ताद बिरमिल्ला खां ने अपनी धुनों से भोलानाथ को मनाया और शंकर शंभू जैसे महान कव्वालों ने "हजरत मोहम्मद सलै-अल्लाह-अले-वसल्लम" की शान में 'नात' गाया। काशी के विश्वनाथ धाम के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं कि 1669 में औरंगजेब ने इसका विध्वंस करने का फरमान जारी किया था। इसी प्रकार उसने मथुरा के केशवदेव मन्दिर को भी क्षति पहुंचाने का आदेश दिया था। बेशक यह उस दौर की राजनीति में राजशक्ति दिखाने की कोई रणनीति रही होगा जबकि औरंगजेब के शासन में पूरे मुगल सम्राटों के शासन के मुकाबले सर्वाधिक 'हिन्दू मनसबदार' थे। मगर यह इतिहास का सच तो है ही अत: मुसलमानों को इसे स्वीकार करना चाहिए और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए फराखदिली दिखानी चाहिए। ज्ञानवापी की दुरो दीवार यही कहती है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई तो इस्लाम की नजर में भी नाजायज है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कमेटी ने यह भी कहा है कि मस्जिद को आसानी से तश्तरी में सजा कर नहीं देंगे। अब जबकि इंसाफ नहीं हो रहा तो सड़कों पर उतरने के हालात भी बन सकते हैं। अभी भी समय है कि दोनों सम्प्रदाय बैठकर मुद्दे को सुलझाएं। अयोध्या की तर्ज पर मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और भूमि भी दी जा सकती है।

असहमति को दबाने पर उतर आये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अरुण श्रीवास्तव इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की विश्वनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने शस्त्रागार को समाप्त करने के बाद, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के मिशन के साथ, अब यह कहावत उछाल रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के लौह पुरुष हैं जो पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और उसकी अखंडता को बरकरार रख सकें।

नि:संदेह, ऐसी दो घटनाएं हैं जो सीधे तौर पर इस मुद्दा को अनुबंधित करती हैंय सबसे पहले, घुसपैठियों का एक झुंड नए संसद भवन में कूद गया और अंदर धुआं बम फेंक दिया, जिससे व्यापक दहशत फैल गईय और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के 143 सदस्यों का निष्कासन जो मोदी की अटल, जीवन से भी बड़ी छवि के दावों का खंडन करता है। बीजेपी इकोसिस्टम का नया मंत्र यह है कि मोदी अजेय हैं, उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती और भारत के पास कोई दूसरा नेता नहीं है जो उनका विकल्प बन सके। दोनों घटनाओं को करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा अति-राष्ट्रवाद के तत्व को उभारने

संसद पर हमला, अब और तब

चंद्रमोहन यह एक इमारत जरूर है पर उससे भी महत्वपूर्ण यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसका प्रतीक है। इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संसद है तो लोकतंत्र है, लेकिन इसी भवन में 13 दिसम्बर को दो नौजवान दर्शक गैलरी से लोकसभा के सदन के बीच कूद पड़े और पकड़े जाने से पहले अंदर धुएं के कनस्तर से पीला धुआं फैलाने में सफल रहे। दो और साथी बाहर पकड़े गए। यह धुआं हानिकारक नहीं था पर अगर उनके पास इसकी जगह बारूद होता तो क्या होता? उस दिन संसद ने 22 वर्ष पहले हुए हमले में संसद की रक्षा करते मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और इसी दिन ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नु ने संसद पर हमला करने की धमकी दी थी पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था लापरवाह पाई गई। अपराधियों को वहां ही पकड़ लिया गया पर सवाल तो है कि हमारे यहां ‘सब चलता है’ की संस्कृति क्यों है कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन की सुरक्षा का कुछ नौजवान मजाक बना गए? जब नया भव्य भवन बनाया गया तो यह बताया गया कि बिल्कुल सुरक्षित होगा, लेकिन कुछ ही महीने में पता चल गया कि संसद बरला, लापरवाह मानसिकता नहीं बदली। इस बार घुसपैठियों के आतंकवादियों के साथ सम्बंध नहीं हैं, न ही वह पेशेवर अपराधी ही हैं, पर अगर होते तो? अब आठ सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन यह भी छुपा है कि संसद में सुरक्षा कर्मियों की 40 प्रतिशत जगह खचली है। यह कैसे हो गया? नई इमारत में दर्शक गैलरी से सांसदों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं जिससे वहां से छलांग लगाना आसान है जबकि पुराने भवन में वह पीछे थी। मुझे याद है कि पहली बार

ठिठुरता गणतंत्र, आहत महामहिम

सर्वमित्रा सुरजन कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। गण कांप रहे हैं, तंत्र पर पाला पड़ गया है। परसाई जी आज

होते तो शायद ठिठुरते गणतंत्र में आहत महामहिम की पकड़-कथा पर भी लिखते कि कैसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोगों के हक मारे जा रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि माननीय मोदीजी क्यों देश में ब्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। बेचारे राम कब से अपने घर के बाहर हैं। सोचने वाली बात है कोई घर से बाहर रहेगा तो कैसे राज कायम करेगा। इसलिए मंदिर में श्री राम का विराजना और संसद में प्रधानमंत्री की आसदी पर नरेंद्र मोदी का विराजना जरूरी है। जब ऐसा होगा, तभी राम राज

कायम होगा। अभी तो घोर कलजुग चल रहा है। सनातन धर्म को चुनौती दी जा रही है। क्या पिछले हुए सीसे अधर्मियों के कान में डालने की जगह नालियों में बहा दिए गए हैं। इसलिए इन्हें महामहिम की पकड़-कथा पर मोदीजी सिखा रहे थे। कितने ज्ञानी और दूरदर्शी हैं वे, हर बात वक्त से पहले समझ जाते हैं। उन्होंने 2001 में ही देख लिया था कि आने वाले राम मंदिर बनवा रहे हैं। बेचारे राम कब से अपने घर के बाहर हैं। सोचने वाली बात है कोई घर से बाहर रहेगा तो कैसे राज कायम करेगा। इसलिए मंदिर में श्री राम का विराजना और संसद में प्रधानमंत्री की आसदी पर नरेंद्र मोदी का विराजना जरूरी है। जब ऐसा होगा, तभी राम राज

2014 में संसद पर हमला करने वाले नौजवानों में से एक अमोल धनराज शिंदे

(2) के अलग–अलग हिस्सों से हैं। कोई उत्तर प्रदेश से तो कोई बिहार से तो कोई कर्नाटक से तो कोई महाराष्ट्र से है। संसद भवन के बाहर पकड़ी गई लड़की नीलम सिंह हरियाणा से है। वह बहुत पढ़ी–लिखी है और सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी जबकि उत्तर प्रदेश का सागर शर्मा 12वीं तक ही पढ़ा है। बिहार का ललित झा टीचर है।



महाराष्ट्र का अमोल धनराज शिंदे सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था जबकि कर्नाटक का मनोरंजन देवाराजे गोड़ा इंजीनियरिंग कर चुका है। इतनी विविध और असमान पृष्ठभूमि वाले यह नौजवान कइठे कैसे हो गए? इन सबके बारे बताया जाता है कि वह फंसबुक पर ‘भगत सिंह फैन क्लब’ से जुड़े हुए हैं। यह दिलचस्प है कि भगत सिंह को फांसी लगे 92 साल के बाद भी वह देश के लिए लोभों की है पर लोगों के लिए भी है। इन लोगों ने यह तमाशा क्यों किया? क्या वह केवल हताशा में सरकार का ध्यान बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ले जाना चाहते थे या कोई और खघ्तरनाक मकद्दस था, यह तो जांच ही बताएगी पर यह दिलचस्प है कि यह सब युवा देश

लोकतंत्र से चुनौती मिल सकती है। नेहरू एंड कंपनी ने आजादी और अधिकारों के नाम पर निचले तबके के लोगों को भी सिर चढ़ा लिया था। तभी तो एक बूढ़ी महिला ने नेहरू के गिरेबान को पकड़ कर सवाल कर लिया था कि आजादी मिली, तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें क्या मिला। बचले में नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रथानमंत्री का गिरेबान पकड़ कर खड़ी हैं।

बताइए भला, ये भी कोई बात हुई कि प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया जाए और वो बुरा भी न माने। बुलबुलवागण वीरों ने ऐसी आजादी की कल्पना कतई नहीं की थी। इसलिए आजादी की लड़ाई की जगह माफी मांगने पर जोर दिया गया। लेकिन इन कांग्रेसियों को नौन समझाए। आजादी के लिए लड़ते रहे, मरते रहे और जब आजादी मिली तो ऐसा लोकतंत्र और संविध्ान ले आए कि नीच–ऊंच सब सपाट करने की बात होने लगी। इसलिए अभी सरकार जितने तरह से हो सके, देश को ये समझा रही है कि असली आजादी 15 अगस्त के बाद मिली है, उसके पहले तो देश नेहरू का युलाम रहा। मोदीजी जो बात–बात में नेहरू की गलतियां निकालते रहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो भी नेहरू के नक्शेकदमों पर चल रहे होते तो फिर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होती। बिचारे ठिठुरते गणों ने कितने सपनों से मोदीजी को एक नहीं दो–दो बार सत्ता पर बिठाया है, ताकि देश में हिंदुओं का शासन कायम हो सके। मोदीजी को जुमलेबाज कहने वाले देशद्रोही ही नहीं गणद्रोही भी हैं। उन्हें मोदीजी को जुमलेबाज कहने की जगह देखना चाहिए कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरुपति,

दिन–रात भगवान की पूजा में लगा दें। पहले के प्रधानमंत्रियों ने, यानी 1947 से लेकर 2014 तक के प्र्थानमंत्रियों ने देश को गुमराह किया कि हम आजाद हैं। पुराने संसद भवन से सेंगोल गायब था, इसलिए सांसदों को इतनी छूट मिली हुई थी कि वे सवाल–जवाब कर सकें। सांसदों को सिर पर चढ़ने देने की गलती नेहरूजी ने खूब की, इसलिए उनके गंजे सिर तक पर संसद में नक्शेकदमों पर चल रहे होते तो फिर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होती। बिचारे ठिठुरते गणों ने कितने सपनों से मोदीजी को एक नहीं दो–दो बार सत्ता पर बिठाया है, ताकि देश में हिंदुओं का शासन कायम हो सके। मोदीजी को जुमलेबाज कहने वाले देशद्रोही ही नहीं गणद्रोही भी हैं। उन्हें मोदीजी को जुमलेबाज कहने की जगह देखना चाहिए कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरुपति,

2014 में संसद पर हमला करने वाले नौजवानों में से एक अमोल धनराज शिंदे

चलो भगत सिंह के रास्ते। पृष्ठभूमि में भगत सिंह की तस्वीर लगा सागर शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है, ‘जिन नौजवानों ने कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज ही अकल से अंधा बनाने की कोशिश हो रही है’, लेकिन क्या यह लोग भगत सिंह और उनकी वैचारिक गहराई को समझते भी हैं? ठीक है उस महान शहीद ने असेम्बली में बम फेंकते

समय कहा था कि ‘बहरे कानों को सुनाने के लिए ऊंचे विस्फोट की जरूरत है’, पर जिन कानों की वह बात कर रहे थे वह फिर्ंगी कान थे। वह साम्राज्यवादी कान थे। वह अपनी संसद में कभी ऐसी हरकत न करते। जिन्होंने संसद में हरकत की है उनके खधिलाफ तो उचित कारंवाई की जानी चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना संसद भवन में, या कहीं और, दोहराई जाए। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि उस जन प्रतिनिधि जिसके गैरजिम्मेदार आचरण के कारण संसद की सुरक्षा और प्रतिष्ठ खघ्तरें में पड़ी है, के प्रति भी उदारता न दिखाई जाए। इन अभियुक्तों को संसद का प्रवेश पास भाजपा के मसूर से सांसद प्रताप सिन्हा ने दिलवाया था। उनपर

कभी अक्षरधाम, कभी केदारनाथ, कहीं न कहीं मोदीजी पूजा–पाठ करते दिख ही जाएंगे। सनातन का महात्म्य इसी में है कि देश का प्रधानमंत्री

लोकतंत्र से चुनौती मिल सकती है। नेहरू एंड कंपनी ने आजादी और अधिकारों के नाम पर निचले तबके के लोगों को भी सिर चढ़ा लिया था। तभी तो एक बूढ़ी महिला ने नेहरू के गिरेबान को पकड़ कर सवाल कर लिया था कि आजादी मिली, तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें क्या मिला। बचले में नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रथानमंत्री का गिरेबान पकड़ कर खड़ी हैं।

बताइए भला, ये भी कोई बात हुई कि प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया जाए और वो बुरा भी न माने। बुलबुलवागण वीरों ने ऐसी आजादी की कल्पना कतई नहीं की थी। इसलिए आजादी की लड़ाई की जगह माफी मांगने पर जोर दिया गया। लेकिन इन कांग्रेसियों को नौन समझाए। आजादी के लिए लड़ते रहे, मरते रहे और जब आजादी मिली तो ऐसा लोकतंत्र और संविध्ान ले आए कि नीच–ऊंच सब सपाट करने की बात होने लगी। इसलिए अभी सरकार जितने तरह से हो सके, देश को ये समझा रही है कि असली आजादी 15 अगस्त के बाद मिली है, उसके पहले तो देश नेहरू का युलाम रहा। मोदीजी जो बात–बात में नेहरू की गलतियां निकालते रहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो भी नेहरू के नक्शेकदमों पर चल रहे होते तो फिर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होती। बिचारे ठिठुरते गणों ने कितने सपनों से मोदीजी को एक नहीं दो–दो बार सत्ता पर बिठाया है, ताकि देश में हिंदुओं का शासन कायम हो सके। मोदीजी को जुमलेबाज कहने वाले देशद्रोही ही नहीं गणद्रोही भी हैं। उन्हें मोदीजी को जुमलेबाज कहने की जगह देखना चाहिए कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरुपति,

दिन–रात भगवान की पूजा में लगा दें। पहले के प्रधानमंत्रियों ने, यानी 1947 से लेकर 2014 तक के प्र्थानमंत्रियों ने देश को गुमराह किया कि हम आजाद हैं। पुराने संसद भवन से सेंगोल गायब था, इसलिए सांसदों को इतनी छूट मिली हुई थी कि वे सवाल–जवाब कर सकें। सांसदों को सिर पर चढ़ने देने की गलती नेहरूजी ने खूब की, इसलिए उनके गंजे सिर तक पर संसद में नक्शेकदमों पर चल रहे होते तो फिर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात कैसे होती। बिचारे ठिठुरते गणों ने कितने सपनों से मोदीजी को एक नहीं दो–दो बार सत्ता पर बिठाया है, ताकि देश में हिंदुओं का शासन कायम हो सके। मोदीजी को जुमलेबाज कहने वाले देशद्रोही ही नहीं गणद्रोही भी हैं। उन्हें मोदीजी को जुमलेबाज कहने की जगह देखना चाहिए कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरुपति,

अब और तब

भी कारंवाई होनी चाहिए। संसद के नियमों के बारे निजी दोस्त / जिसे मैं निजी तौर पर जानता हूं, और मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं” इसलिए जो हुआ उसकी जिम्मेवारी से प्रताप सिन्हा बच नहीं सकते पर अभी तक उनके खिलाफ कोई जांच हुई हो, इसकी कोई खबर नहीं। अगर कोई बड़ी साजिश है तो सांसद से भी पूछताछ होनी चाहिए। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को अपना संसदीय लॉगइन साझा करने के अपराध में संसद से निष्कासित किया गया था। निश्चित तौर पर प्रताप सिन्हा का अपराध महुआ मोइत्रा से बहुत अधिक गम्भीर है। उनके कारण संसद की सुरक्षा भारी खतरें में पड़ गई थी। 22 साल पहले 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हमला हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि वर्तमान घटना उससे भी अधिक गम्भीर है। कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव वी. बालाचन्‍द्रम लिखते हैं, “इस बार जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी अपराधी संसद के दिल तक पहुंचने में सफल रहे हैं। यह इसे 2001 की घटना से अधिक गम्भीर बना देती है, क्योंकि तब आतंकवादी इमारत के अंदर तक पहुंचने में सफल नहीं हुए थे।” उनका कहना है कि अगर गैस के कनस्तर की जगह उनके पास ग्रेनेड होता तो क्या हालत होती? पर मेरी राय उनसे अलग है, क्योंकि ग्रेनेड या कोई हथियार नहीं थे इसलिए यह घटना उतनी गम्भीर नहीं है। 2001 में तो बाकायदा पाकिस्तान प्रशि्षित आतंकवादी हमला हुआ था। उस दिन आतंकवादी सफेद एम्बेसेडर कार में आए थे। कार में ड्राइवर और गैरजिम्मेदार आचरण के कारण संसद की सुरक्षा और प्रतिष्ठ खघ्तरें में पड़ी है, के प्रति भी उदारता न दिखाई जाए। इन अभियुक्तों को संसद का प्रवेश पास भाजपा के मसूर से सांसद प्रताप सिन्हा ने दिलवाया था। उनपर

कभी आरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी मेन गेट बंद करने में सफल हो गई थी। वह खुद वहां ही शहीद हो गई, उन्हें 11 गोलियां लगी थीं। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई नुक्‍सान नहीं हुआ। कोई हथियार नहीं थे, इसीलिए मैं समझता हूँ कि घटना उतनी गम्भीर नहीं थी, पर सुरक्षा चुक अधिक गम्भीर थी, क्योंकि घुसपैठिए अन्दर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन घटनाओं के बाद जो हुआ वह भी पहली घटना से बहुत अलग थी। 22 साल पहले जब आतंकवादी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री वाजपेयी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संसद से घर लौट चुके थे। गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी और लगभग 200 सांसद वहां मौजूद थे। जब सोनिया गांधी को हमले बारे पता लगा तो उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री वाजपेयी को फोन कर पूछा, “आप ठीक हो हैं”, वाजपेयी का जवाब दिया, “मेरा छोड़िए आप ठीक है न?” अगले दिन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने संसद में कहा कि “अगर विपक्ष की नेता को प्रधानमंत्री की चिन्ता है तो उसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ है”। यह भाईचारा अब नजर नहीं आता। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों को पत्र लिख होता तो क्या हालत होती? पर मेरी राय उनसे अलग है, क्योंकि ग्रेनेड या कोई हथियार नहीं थे इसलिए यह घटना उतनी गम्भीर नहीं है। 2001 में तो बाकायदा पाकिस्तान प्रशि्षित आतंकवादी हमला हुआ था। उस दिन आतंकवादी सफेद एम्बेसेडर कार में आए थे। कार में ड्राइवर और गैरजिम्मेदार आचरण के कारण संसद की सुरक्षा और प्रतिष्ठ खघ्तरें में पड़ी है, के प्रति भी उदारता न दिखाई जाए। इन अभियुक्तों को संसद का प्रवेश पास भाजपा के मसूर से सांसद प्रताप सिन्हा ने दिलवाया था। उनपर

लोकतंत्र से चुनौती मिल सकती है। नेहरू एंड कंपनी ने आजादी और अधिकारों के नाम पर निचले तबके के लोगों को भी सिर चढ़ा लिया था। तभी तो एक बूढ़ी महिला ने नेहरू के गिरेबान को पकड़ कर सवाल कर लिया था कि आजादी मिली, तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें क्या मिला। बचले में नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको ये मिला है कि आप देश के प्रथानमंत्री का गिरेबान पकड़ कर खड़ी हैं।

पुराणों, मनु स्मृति में इन्हें दबाकर रखने कहा गया है तो फिर इस दिख ही जाएंगे। सनातन का महात्म्य इसी में है कि देश का प्रधानमंत्री



कभी अक्षरधाम, कभी केदारनाथ, कहीं न कहीं मोदीजी पूजा–पाठ करते दिख ही जाएंगे। सनातन का महात्म्य इसी में है कि देश का प्रधानमंत्री

कभन के भीतर आंख मिचमिचाने की बिमिर्क्री करनी हो या बाहर ताली बजा–बजाकर सवाल पूछना हो, ये सब मोदीजी ही कर सकते हैं। किसी और को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। इसलिए इस घटना से राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के साथ–साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई नेता आहत हो गए। यहां तक कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने भी इस पर अपनी निराशा प्रकट कर दी।अब लग रहा है कि वार्कई देश नए सिरे से आजाद हुआ है। क्योंकि अब लोगों को कपड़े देखकर दानों सदनों से आवाज उठाने वाले सांसदों को बाहर किया गया। लेकिन शूल में सवाल पूछे गए और सरकार ने जवाब दिए। हद ही हो गई थी। इसलिए मोदीजी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाकर बिल्कुल नीति किया, तभी तो नीति लिए कैसे वे दिन–रात एक करके काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब, एक के बाद दूसरा मंदिर बनवाने से है। अयोध्या की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब काशी, मथुरा कतार में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कभी महाकाल, कभी तिरुपति,

2014 में संसद पर हमला करने वाले नौजवानों में से एक अमोल धनराज शिंदे

